



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05022020-215927
CG-DL-E-05022020-215927

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 31, 2020/माघ 11, 1941

No. 31]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 31, 2020/MAGHA 11, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच की शुरुआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2020

(एम टी आर प्रकरण संख्या ओआई.11/2019)

विषय: यूरोपीय संघ और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "नायलॉन फिलामेंट यार्न" पर लागू निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क के उत्पाद क्षेत्र की पुनरीक्षा करने के लिए मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत।

फा. सं. 7/30/2019-डीजीटीआर.—1.मैसर्स एक्वाफिल एसपीए (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे "अधिनियम" कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जांच, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां "नियमावली" कहा गया है) के अनुसार, उत्पाद क्षेत्र की पुनरीक्षा करने और पाटनरोधी शुल्क जांच के क्षेत्र से बहिष्कृत बल्क यूरोपीय संघ और वियतनाम (जिन्हें यहां "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नायलोन फिलामेंट यार्न (मल्टी फिलामेंट) (जिन्हें यहां "संबद्ध वस्तु" "विचाराधीन उत्पाद" या पीयूसी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क में बल्क सतत फिलामेंट की परिभाषा में संशोधन करने के लिए सीमित मध्यावधि पुनरीक्षा जांच की शुरुआत करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे यहां प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। उक्त जांच में अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/33/2016-डीजीएडी दिनांक

06.08.2018 के अनुसार जारी किए गए थे और अधिसूचना संख्या 50/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 5 अक्टूबर, 2018 के अनुसार पाटनरोधी शुल्क लागू किया गया था। सीमाशुल्क केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित यूरोपीय संघ और वियतनाम (जिन्हें यहां संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नायलॉन फिलामेंट यार्न (मल्टी फिलामेंट) (जिन्हें यहां “संबद्ध वस्तु” कहा गया है) पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश की थी।

विचाराधीन उत्पाद

2. उत्पाद, जिस पर पाटनरोधी उपाय लागू है, नायलॉन या पॉलीएमिड्स के सिंथेटिक मल्टी फिलामेंट यार्न हैं जैसे कि फ्लैट यार्न – ट्विस्टड और/ अथवा अनट्विस्टड, क्रिम्पड यार्न, पूरी तरह से ड्रॉन यार्न (एफडीवाई), स्पिन ड्रॉन यार्न (एसडीवाई), पूर्णतः ओरिएंटिड यार्न (एफओवाई), हाई ओरिएंटिड यार्न (एचओवाई), आंशिक रूप से ओरिएंटिड यार्न (पीओवाई), टेक्चर्ड यार्न - ट्विस्टड और/ अथवा अनट्विस्टड और डाई यार्न, सिंगल, डबल, मल्टीपल, फोल्डिड या केबलड, सीमाशुल्क उपशीर्ष संख्या 5402 के तहत अध्याय 54 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य। उत्पाद में नायलॉन फिलामेंट यार्न या पॉलीएमाइड यार्न के सभी रूपांतर शामिल हैं जैसे कि फ्लैट/ टेक्सचर्ड/ ट्विस्टड /अनट्विस्टड, ब्राइट / सेमी डल/ फुल डल (अथवा उनके रूपांतर), ग्रे/ कलर्ड/ डाइड (अथवा उनके रूपांतर), सिंगल/डबल/मल्टीपल/ फोल्डिड/ केबलड (अथवा उनके रूपांतर) चाहे वे आकार वाले हों अथवा नहीं, लेकिन इनमें नायलॉन के उच्च टिनासिटी यार्न शामिल नहीं हैं। विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में सभी मानव निर्मित फिलामेंट यार्न शामिल नहीं किए गए हैं जिनमें नायलॉन अथवा पॉलीएमिड्स और मोनो फिलामेंट यार्न, नायलॉन का हाई टिनासिटी यार्न, बीसीएफ (बल्क कांटीन्युअस फिलामेंट) यार्न शामिल हैं/ बी सी एफ यार्न क्रिम्पड नायलॉन फिलामेंट यार्न है, जिसमें लगभग 4 सेंटी न्युटन डिसेटैक्स और हाई डेनाइरेज (लगभग 650 से 1650 डेसीटैक्स) की उच्च टेनासिटी शामिल है और यह सामान्यतः कालीनों के निर्माण में प्रयुक्त होता है।
3. आवेदक ने डेनाइरेज की उच्च सीमा को 1650 डेसीटैक्स से परिवर्तित कर 10,000 डेसीटैक्स करने के द्वारा बी एस एफ की परिभाषा में संशोधन करने के लिए एक सीमित मध्यवर्ती पुनरीक्षा अनुरोध दायर किया है।
4. अतः, वर्तमान पुनरीक्षा केवल बी सी एफ की परिभाषा में संशोधन की आवश्यकता की जांच करने के सीमित प्रयोजन के लिए है जिसे मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था।

पुनरीक्षा के लिए आधार

5. निवेदित आधार निम्नानुसार हैं :-
 - i. आवेदक की अब 1650 डेसीटैक्स से 10,000 डेसीटैक्स तक के अतिरिक्त में डेनियरेज सहित बी एस एफ यार्न का विनिर्माण करने की क्षमता है। मूल जांच की जांच की अवधि के तत्पश्चात की अवधि के दौरान भारत को उच्च डेनियरेज के साथ बी एस एफ के निर्यात के आरंभ होने का दावा किया गया है।
 - ii. मूल जांच के समय, घरेलू उद्योग अर्थात् मै. जे सी टी लिमिटेड, मै. गुजरात पॉलीफिल्मस प्रा. लिमि., मै. गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर्स और केमिकल्स लिमि., मै. प्रफुल्ल ओवरसीज प्रा. लिमि. और ए वाई एम सिनटैक्स (विगत में वेलस्पन सिंटेक्स के रूप में ज्ञात) ने प्रस्तुत किया था कि वे बीसीएफ का विनिर्माण या विक्रय नहीं करते।
 - iii. 10,000 डेसीटैक्स तक डेनियरेज के साथ बीसीएफ के निवेश की लागत या उत्पादन की लागत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि आवेदक के पास यह विनिर्माण क्षमता हमेशा उपलब्ध रहा है और इसे प्रयोक्ता की मांग के रूप में वर्तमान उत्पादन श्रृंखला के साथ उत्पादित किया जा सकता है।

प्रक्रिया

6. लागू उपाय की समीक्षा को अनिवार्य बनाने वाली परिस्थितियों की ओर संकेत करते हुए, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के संबंध में, प्राधिकारी ने अब विचार किया है कि ऊपर दिए गए (संशोधित) अधिनियम, 1995 की धारा 9(क) के प्रावधानों की शर्तों में, लागू वर्तमान पाटनरोधी उपायों से बहिष्कृत बीसीएफ उत्पादन के क्षेत्र और विशिष्टताओं तक सीमित दिनांक 06.08.2018 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/33/2016-डीजीएडी और दिनांक 5 अक्टूबर, 2018 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 50/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा लागू निश्चित पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा उचित है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आवेदक मै. एक्वाफिल एसपीए ने मध्यावधि समीक्षा की आवश्यकता को स्थापित करने के लिए प्रथमदृष्टया साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ने यूरोपीय संघ और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “नायलॉन फिलामेंट यार्न” पर लागू

निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की एक मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत की है जो उक्त पाटनरोधी शुल्क के उत्पाद क्षेत्र तक सीमित है।

संबद्ध देश

7. वर्तमान जांच में शामिल देश यूरोपीय संघ और वियतनाम है।

जांच की अवधि (पी ओ आई)

8. चूंकि, आवेदन विचाराधीन उत्पाद के एक विशिष्ट प्रकार के बहिष्करण के सीमित प्रयोजन हेतु प्रस्तुत किया गया है, प्राधिकारी ने पाटन और क्षति की मात्रा का मूल्यांकन करने का प्रस्ताव नहीं किया है, इसलिए, पी ओ आई का निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं है।

सूचना प्रस्तुत करना

9. संबद्ध देशों में निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के माध्यम से उनकी सरकार, से संबंधित भारत में संबद्ध वस्तुओं से संबंधित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र और तरीके में सभी संगत सूचना दायर कर सकें।
10. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र और तरीके में जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकते हैं। सूचना/अनुरोध निम्नलिखित को प्रस्तुत किए जाएं:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
व्यापार उपचार महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
भारत सरकार
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001

11. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार से यह अनुरोध है कि वह अन्य पक्षकारों को उसका अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध करायें।

समय-सीमा

12. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित में दी जानी चाहिए ताकि वह नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी को पहुँच जाए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उपर्युक्त नियमावली की व्याख्या के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाए जाने संबंधी सूचना उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुई मानी जाएगी जिसको वह प्राधिकारी द्वारा भेजी गई थी अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधि को भेजी गई थी। यदि कोई सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है अथवा सूचना अपूर्ण प्राप्त होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं।
13. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपने हित (हितों की प्रकृति सहित) सूचित करें और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

14. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (परिशिष्ट/उससे संलग्न अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को, यदि उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा किया गया है तो उसे दो अलग-अलग सेटों में दायर करना अपेक्षित है:
 - i. गोपनीय के रूप में चिह्नित एक सेट (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, सूची आदि), और
 - ii. अगोपनीय के रूप में चिह्नित दूसरा सेट (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, सूची आदि)।
15. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अनुरोध प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित होने चाहिए। इस प्रकार के चिह्नों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना

जाएगा और प्राधिकारी उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने हेतु स्वतंत्र होंगे। दोनों रुपांतरों की सॉफ्ट प्रतियां भी प्रत्येक के दो (2) सेटों की हार्ड प्रतियों के साथ प्रस्तुत की जानी अपेक्षित होंगी।

16. गोपनीय रुपांतर में वह सभी सूचना होगी जो प्रकृति से गोपनीय और/अथवा अन्य सूचना है जिसको सूचना देने वाला गोपनीय होने का दावा करता है। जिस सूचना को प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना के संबंध में अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, उस सूचना के संबंध में सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ सही कारण का विवरण प्रदान करें कि उस सूचना का प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता।
17. अगोपनीय रुपांतर को गोपनीय सूचना के साथ अधिमानतः उस सूचना के आधार पर सूचीबद्ध अथवा ब्लैंक आउट (यदि सूचीकरण व्यवहार्य नहीं है) तथा सारांश का प्रदर्श होना अपेक्षित है जिसके आधार पर गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश गोपनीय आधार पर दी गई सूचना के सार की उपयुक्त समझ देने के लिए पर्याप्त व्यौरे में होने चाहिए। तथापि, अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह दर्शा सकते हैं कि यह सूचना सारांश के लिए संवेदनशील नहीं है; सारांश क्यों संभव नहीं है, इसका एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप दिया जाना चाहिए।
18. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा रद्द कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा यदि सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक करने का अनिच्छुक है अथवा सामान्य रूप में या सारांश रूप में उसे प्रकट करने के लिए प्राधिकृत नहीं करना चाहता तो वे उसकी अनदेखी कर सकते हैं।
19. किसी सार्थक अगोपनीय रुपांतर के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में अच्छे कारण के विवरण के बिना किया गया कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।
20. प्राधिकारी संतुष्ट होने पर तथा दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करने पर उस सूचना को प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसे प्रकट नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

21. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रुपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

22. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना देने से इंकार करता है अथवा अन्यथा उपयुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता अथवा जांच में काफी बाधा डालता है, तो प्राधिकारी उनके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को आवश्यक समझी जाने वाली सिफारिश कर सकते हैं।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2020

MTR Case No. 11/2019

Subject: Initiation of Mid-Term Review to review the product scope of definitive Anti-Dumping duty imposed on 'Nylon Filament Yarn' originating in or exported from European Union and Vietnam.

1. **F.No.7/30/2019-DGTR.**—M/s. Aquafil SpA (hereinafter referred to as the 'Applicant') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Act')

and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the 'Rules') for initiation of limited mid-term review investigation to review the product scope and amend the definition of Bulk Continuous Filament in the antidumping duty investigation on imports of Nylon Filament Yarn (Multi Filament) (hereinafter referred to as "subject goods" or "product under consideration" or PUC) originating or exported from the European Union and Vietnam (hereinafter also referred to as subject countries). Final Findings in the said investigation were issued vide Notification No. 14/33/2016-DGAD dated 06.08.2018 and anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Custom Notification No. 50/2018-Customs (ADD) dated 5th October, 2018.

Product under Consideration

2. The product on which the anti-dumping measures is in force is Synthetic multi filament yarns of Nylon or Polyamides, such as flat yarn - twisted and/or untwisted, crimped yarn, fully drawn yarn (FDY), spin drawn yarn (SDY), fully oriented yarn (FOY), high oriented yarn (HOY), partially oriented yarn (POY), textured yarn – twisted and/or untwisted, and dyed yarn, single, double, multiple, folded or cabled, classifiable within Chapter 54 under customs subheading no. 5402. The product includes all variants of Nylon Filament Yarn or Polyamide Yarns such as flat/ textured/ twisted/ untwisted, bright/semi-dull/full-dull (or variants thereof), grey/ colored/ dyed (or variants thereof), single/double/ multiple/folded/cabled (or variants thereof), whether or not sized, but excludes high tenacity yarn of nylon. Specifically excluded from the scope of product under consideration are all man-made filament yarns not having Nylon or Polyamides and mono filament yarn, high tenacity yarn of nylon, BCF (Bulk Continuous Filament) yarn. BCF yarn is crimped nylon filament yarn which has high tenacity of approximately 4 centi newton decitex and high denierage (approx. 650 to 1650 decitex) and is normally used in carpet making.
3. The Applicant has filed a limited mid-term review request for amendment in the definition of BCF by changing the upper limit of denierage from 1650 decitex to 10,000 decitex.
4. The present review is, therefore, only for the limited purpose of investigating the need for amending definition of BCF which was excluded from the scope of the product under consideration in the original investigation.

Grounds for Review

5. The grounds pleaded for review are as follows:
 - i. The Applicant now has the capacity to manufacture the BCF yarn with denierage in excess of 1650 decitex up to 10,000 decitex. The export of BCF with higher denierage to India is claimed to have commenced during the period subsequent to the period of investigation of original investigation.
 - ii. At the time of original investigation, the Domestic Industry i.e M/s JCT Limited, M/s Gujarat Polyfilms Pvt. Ltd, M/s Gujarat State Fertilizers and Chemicals Ltd., M/s Praful Overseas Pvt. Ltd. & AYM Syntex (Formerly known as Welspun Syntex) had submitted that they do not manufacture or sell BCF.
 - iii. There is no change in the cost of investment or cost of production of BCF for manufacturing BCF with denierage upto 10,000 decitex since such manufacturing capacity has always been available with the Applicant and same can be produced with the existing production lines on the demand of customers.

Procedure

6. Having regard to the information provided by the Applicant indicating circumstances necessitating a review of the measure in force, the Authority now considers that a mid-term review of the Final Findings No. 14/33/2016-DGAD dated 06.08.2018 and the Customs Notification No. 50/2018-Customs (ADD) dated 5th October, 2018 limited to the specification of the product BCF excluded from existing anti-dumping measures is appropriate, in terms of the provision of Section 9(A) of Customs Tariff (Amendment) Act 1995 read with Rule 23 (1) supra. The Authority also notes that the Applicant M/s Aquafil SpA has provided prima facie evidence to establish the need for mid-term review. Accordingly, the Authority initiates a mid- term review of definitive Anti-Dumping Duty imposed on 'Nylon

Filament Yarn' originating in or exported from the European Union and Vietnam, limited to the product scope.

Subject Countries

7. The countries involved in the present investigations are European Union and Vietnam.

Period of Investigation (POI)

8. Since the application is for limited purpose of change of specification of product excluded from the product under consideration, the Authority does not propose to evaluate either the quantum of dumping and injury, and therefore, stipulation of POI is not required.

Submission of Information

9. The exporters in the subject countries, their government through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
10. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below. The information/ submission may be submitted to:

The Designated Authority

Directorate General of Trade Remedies

Ministry of Commerce & Industry

Department of Commerce

Government of India

4th Floor, Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street

New Delhi-110001

11. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

12. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
13. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

14. The parties making any submission (including Appendices/Annexes attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:
- one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
 - the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).
15. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be

required to be submitted, along with the hard copies in two (2) sets of each.

16. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
17. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarised depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
18. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
19. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
20. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

21. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

22. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority